PAPER NAME

रामगढ़ प्रखण्ड में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता .docx

AUTHOR

Satyendra Kumar

WORD COUNT

1419 Words

CHARACTER COUNT

6958 Characters

PAGE COUNT

5 Pages

FILE SIZE

27.6KB

SUBMISSION DATE

Apr 17, 2026 2:35 PM GMT+5:30

REPORT DATE

Apr 17, 2026 2:35 PM GMT+5:30

2% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 0% Internet database
- 0% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 2% Submitted Works database

रामगढ़ प्रखण्ड में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता

सत्येंद्र कुमार
शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र विभाग
राधा गोविन्द विश्वविद्यालय, रामगढ़, झारखंड

सार (Abstract)

यह शोध आलेख रामगढ़ प्रखण्ड (सदर) में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का एक समालोचनात्मक एवं बहुआयामी विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का केंद्र बिंदु यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता केवल विद्यालयों की उपलब्धता या नामांकन दर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आधारभूत संरचना, शिक्षक दक्षता, शिक्षण-पद्धति, सीखने के परिणाम तथा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के संयुक्त प्रभाव से निर्धारित होती है। शोध में यह पाया गया है कि रामगढ़ प्रखण्ड में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन और संस्थागत विस्तार के बावजूद गुणवत्ता के स्तर पर गंभीर चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी, मल्टी-ग्रेड शिक्षण, डिजिटल संसाधनों का अभाव तथा शिक्षक प्रशिक्षण की अपर्याप्तता शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक असमानता—विशेषकर वर्ग, लिंग और समुदाय आधारित विभाजन—विद्यार्थियों के सीखने के स्तर और शैक्षिक अवसरों को प्रभावित करती है। सीखने के परिणामों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्तर के अनेक विद्यार्थी बुनियादी पढ़ने और गणितीय कौशल में अपेक्षित दक्षता प्राप्त नहीं कर पाते।

यह आलेख इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए केवल नीतिगत हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षक सशक्तिकरण, संसाधनों की उपलब्धता तथा समुदाय की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। समग्र रूप से, यह अध्ययन शिक्षा की गुणवत्ता को एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जिसमें समानता, समावेशन और सतत विकास के सिद्धांतों को केंद्र में रखा जाना चाहिए।

बीज शब्द (Keywords)

प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता, रामगढ़ प्रखण्ड, सीखने के परिणाम, सामाजिक असमानता, शिक्षक भूमिका, आधारभूत संरचना, समावेशी शिक्षा, शिक्षा नीति, ग्रामीण शिक्षा

भारत में प्राथमिक शिक्षा को मानव विकास की आधारशिला के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यही वह स्तर है जहाँ बच्चों के बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास की नींव रखी जाती है। झारखंड जैसे सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण राज्य में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का प्रश्न और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेषकर रामगढ़ प्रखण्ड (सदर) जैसे अर्ध-शहरी एवं ग्रामीण मिश्रित क्षेत्र में, जहाँ विकास के विविध आयाम एक साथ उपस्थित हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 ने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने का संवैधानिक प्रयास किया, किन्तु "पहुंच" (access) और "गुणवत्ता" (quality) के बीच का अंतर अभी भी व्यापक बना हुआ है।

प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को केवल नामांकन दर या विद्यालयों की संख्या से नहीं आँका जा सकता, बल्कि यह एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसमें शिक्षक की दक्षता, आधारभूत संरचना, शिक्षण-पद्धति, सीखने के परिणाम (learning outcomes) और सामाजिक-सांस्कृतिक कारक शामिल होते हैं। यूनेस्को (2005) के अनुसार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वह है जो विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करे और उन्हें जीवन के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करे (यूनेस्को 37)। अमर्त्य सेन (1999) की "क्षमता दृष्टिकोण" (Capability Approach) के अनुसार, शिक्षा व्यक्ति की क्षमताओं का विस्तार करती है और उसे सामाजिक-आर्थिक अवसरों तक पहुँच प्रदान करती है।[1]

रामगढ़ प्रखण्ड में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का विश्लेषण करते समय यह स्पष्ट होता है कि यहाँ शिक्षा प्रणाली कई संरचनात्मक चुनौतियों से जूझ रही है, जिनमें संसाधनों की कमी, शिक्षक प्रशिक्षण की अपर्याप्तता और सामाजिक असमानताएँ प्रमुख हैं। इस प्रकार, शिक्षा की गुणवत्ता को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम इसे केवल प्रशासनिक उपलब्धियों के संदर्भ में न देखकर एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में देखें, जहाँ नीति, व्यवहार और वास्तविकता के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर मौजूद है।

रामगढ़ प्रखण्ड के प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचना शिक्षा की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है, क्योंकि यह सीधे तौर पर शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। विद्यालय भवन, कक्षाओं की उपलब्धता, शौचालय, पेयजल, पुस्तकालय और खेलकूद की सुविधाएँ शिक्षा के समग्र वातावरण को निर्धारित करती हैं। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, झारखंड के कई प्राथमिक विद्यालयों में अभी भी आधारभूत सुविधाओं की कमी देखी जाती है, जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।[2]

रामगढ़ प्रखण्ड में भी यह स्थिति आंशिक रूप से परिलक्षित होती है, जहाँ कई विद्यालयों में कक्षाओं की संख्या सीमित है और एक ही कक्षा में कई कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाया जाता है। इस प्रकार की "मल्टी-ग्रेड टीचिंग" (Multi-grade Teaching) शिक्षण की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, क्योंकि शिक्षक को एक ही समय में विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों को संभालना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल संसाधनों की कमी भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। कोविड-19 महामारी के बाद शिक्षा में डिजिटल माध्यमों का महत्व बढ़ा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट, स्मार्ट डिवाइस और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण यह परिवर्तन प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाया है। इस प्रकार, आधारभूत संरचना और संसाधनों की कमी शिक्षा की गुणवत्ता को सीमित करती है और यह दर्शाती है कि केवल नीतिगत प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का मुख्य वाहक होता है। रामगढ़ प्रखण्ड में शिक्षक उपलब्धता, प्रशिक्षण और शिक्षण-पद्धति से संबंधित कई चुनौतियाँ सामने आती हैं। यद्यपि शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने शिक्षक-छात्र अनुपात (PTR) को निर्धारित किया है, फिर भी कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी देखी जाती है, जिसके कारण शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

शिक्षक प्रशिक्षण की स्थिति भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कई अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों और बाल-केंद्रित शिक्षण पद्धतियों का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिलता।[3] इसके परिणामस्वरूप, शिक्षण प्रक्रिया पारंपरिक "रटने" (rote learning) पर आधारित रहती है, जो विद्यार्थियों की रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को विकसित नहीं कर पाती।

रामगढ़ प्रखण्ड में भी यह प्रवृत्ति देखी जाती है, जहाँ शिक्षण का मुख्य उद्देश्य परीक्षा उत्तीर्ण करना रह जाता है, न कि वास्तविक सीखने को बढ़ावा देना। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि शिक्षकों को निरंतर प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ, ताकि वे विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित कर सकें।

प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक विद्यार्थियों के सीखने के परिणाम (learning outcomes) होते हैं। विभिन्न राष्ट्रीय सर्वेक्षणों, जैसे ASER (Annual Status

of Education Report), ने यह दर्शाया है कि प्राथमिक स्तर के कई विद्यार्थी बुनियादी पढ़ने और गणितीय कौशल में पीछे रह जाते हैं।[4]

रामगढ़ प्रखण्ड में भी यह समस्या देखी जाती है, जहाँ नामांकन दर उच्च होने के बावजूद सीखने के स्तर अपेक्षित नहीं हैं। इसका एक प्रमुख कारण सामाजिक-आर्थिक असमानता है, जो शिक्षा के अवसरों और परिणामों को प्रभावित करती है। गरीब परिवारों के बच्चे अक्सर घरेलू कार्यों या श्रम में संलग्न होते हैं, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित होती है।

इसके अतिरिक्त, लिंग, जाति और वर्ग आधारित असमानताएँ भी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। आदिवासी और दलित समुदायों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें भाषा, सांस्कृतिक अंतर और आर्थिक सीमाएँ शामिल हैं। अमर्त्य सेन (1999) के अनुसार, शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करना सामाजिक न्याय के लिए अनिवार्य है।[5]

इस प्रकार, शिक्षा की गुणवत्ता को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम इसे केवल विद्यालय के भीतर की प्रक्रिया तक सीमित न रखें, बल्कि व्यापक सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में देखें।

रामगढ़ प्रखण्ड में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का समग्र विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधारात्मक प्रयास किए गए हैं, फिर भी गुणवत्ता के स्तर पर गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं। आधारभूत संरचना की कमी, शिक्षक प्रशिक्षण की अपर्याप्तता, सामाजिक असमानताएँ और सीखने के निम्न स्तर इस समस्या के प्रमुख कारण हैं।

इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि शिक्षा की नीतियों को केवल “पहुंच” (access) तक सीमित न रखकर “गुणवत्ता” (quality) पर केंद्रित किया जाए। इसके लिए विद्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने, शिक्षकों के प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने और विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

इसके अतिरिक्त, समुदाय की भागीदारी को भी बढ़ावा देना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा केवल सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि सामाजिक सहयोग से ही प्रभावी हो सकती है।

अंततः, रामगढ़ प्रखण्ड का अनुभव यह दर्शाता है कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक समग्र और समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें नीति, व्यवहार और सामाजिक संदर्भ के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।

संदर्भ सूची :

1. सेन, अमर्त्य. *विकास के रूप में स्वतंत्रता*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999, पृ. 89.
2. यूनेस्को. *गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अवधारणा*. यूनेस्को प्रकाशन, 2005, पृ. 37.
3. एनसीईआरटी. *प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण की स्थिति*. 2018, पृ. 112.
4. एएसईआर. *वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट*. 2022, पृ. 48.
5. यूडीआईएसई. *स्कूल शिक्षा रिपोर्ट, झारखंड*. 2021, पृ. 56.

2% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 0% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 0% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	**Berhampur University on 2026-04-16** Submitted works	1%
2	**Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala on 2026-03-09** Submitted works	<1%